ने अपने अनुमान के अनुसार कहा है कि इस बार 12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस के लिये विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र से 31 हजार करोड़ रुपये की मांग की है। हमारे प्रदेश हरियाणा ने भी 1800 करोड़ रुपये की मांग की थी।

गत सितम्बर माह में एक निरीक्षण दल हरियाणा प्रदेश के दौरे पर गया और उसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दी। उसके बाद हरियाणा को केवल 109 करोड़ रुपया दिया गया। इस रुपये से हरियाणा के किसान जो सूखे से प्रभावित हैं, को राहत नहीं दी जा सकती।

सभापति महोदया, यह बड़े अफसोस की बात है कि सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हिसार गये जहां उन्होंने बयान दिया कि हरियाणा सरकार ने राहत कार्यों के लिये कोई मांग नहीं की। यह सदन इस बात का गवाह है कि पिछली बार जब सूखे और बाढ़ पर यहां चर्चा हुई थी, श्री अजय चौटाला ने उस चर्चा की शुरूआत करते हुये मांग की थी, जो रिकार्ड पर है। हमारे नेता स्व० चौ० देवी लाल की नीतियों पर चलने वाली हरियाणा सरकार किसानों के विरोध में कैसे काम कर सकती है? माननीय मंत्री जी का बयान अफसोसनाक है।

सायं 6.54 बजे

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने 1800 करोड़ रुपये की मांग की थी। अगर माननीय मंत्री जी कहें कि नहीं की तो आज हम इस बात की मांग करते हैं कि वह हरियाणा प्रदेश को 1800 करोड़ रुपये दे। यदि किसानों के हितैषी होने का दावा करने वाले मंत्री इस तरह की गलत बयानबाजी करें तो अफसोस होता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम में सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश के किसानों को राहत मिल सके, उसके लिए जो धनराशि की मांग हमारी हरियाणा सरकार ने की है, वह धनराशि उसे जल्दी से जल्दी दी जाए। यह मेरी एक साधारण सी विनती हैं लेकिन इसके साथ मेरी एक अपील भी है, यह एक साधारण सामूहिक अपील है। यह वक्त की बात है, लेकिन अगर हम इतिहास को उठाकर देखें, जैसा कि हम अपने दादा, दादी और नाना नानी से सुनते आये हैं कि कभी वह वक्त था कि पेड़ों के छिलके उतार कर लोग अकाल में खाते थे। आज स्वयं मंत्री जी ने माना है कि हमारे यहां अनाज के भंडार भरे हैं। हमारे यहां अनाज की कोई कमी नहीं है। आज हमें सिर्फ 23 मिलियन टन अनाज की जरूरत है, जबकि करीब 69-70 मिलियन टन का हमारे यहां भंडार है।

हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो केन्द्रीय पूल में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा अनाज के भंडार भरने का काम करता हैं उसके बारे में मैं कहूंगा आज हमारी जल प्रबंधन की स्थिति ठीक नहीं है। बड़ी-बड़ी योजनाएं लम्बित पड़ी हैं। यदि हम कावेरी और गंगा के बेसिन को जोड़ दें तो उससे देश को बहुत फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 15 जनवरी के पहले एस०वाई०एल० बन जानी चाहिए। लेकिन आज वहां एक भी ईंट नहीं लगी हैं क्या इतने कम समय में एस०वाई०एल० कैनाल का निर्माण कार्य पूरा हो पायेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो जल परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं, खासकर एस०वाई०एल० की परियोजना निर्धारित समयावधि में पूरी हो जाए ताकि हरियाणा के किसानों, विशेष रूप से दक्षिणी हरियाणा में महेन्द्रगढ़ और नारनौल के किसानों को बहुत फायदा होगा। इसमें किसी प्रदेश का आपस में कोई मामला नहीं हैं यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।

अंत में, मैं यही कहूंगा कि कई बार शासक और प्रशासक इस बात से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं हम नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तो उससे व्यवस्था को सुधार पायेंगे या नहीं सुधार पायेंगे। लेकिन मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जनहित में अगर कड़ाई से नियम पालन किया जाए, जैसे एस०वाई०एल० कैनाल की बात हैं अगर उसमें कड़ाई से नियम पालन किया जाए तो देश का काफी उद्धार हो सकेगा। आप मुझे बार-बार इशारा कर रहे है कि समय समाप्त हो गया है। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा और सभी से अपील करूंगा कि सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सबको मिल-जुलकर काम करना चाहिए। इसमें जहां प्रतिपक्ष की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, वहीं सरकार की ज्यादा जिम्मेदारियां बनती हैं। इसमें आम गरीब आदमी ज्यादा पिसता है इसलिए आम गरीब लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधान मंत्री जी इंटरवीन करेंगे।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा का उत्तर देने के खड़ा नहीं हुआ हूं, चर्चा जारी रहेगी।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : सर, प्रधान मंत्री जी के इंटरवेशंन के बाद हाउस में कोई नहीं बैठेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं रहने वाला हूं, मैं सुनूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चर्चा का उत्तर मेरे सहयोगी कृषि मंत्री जी देंगे। चर्चा के बीच में यादव जी ने सूखे से उत्पन्न परिस्थिति पर सदन के सामना कुछ जानकारी प्रस्तुत की थी। उससे यह बात स्पष्ट होती है कि सूखा बहुत व्यापक है, गंभीर है और उसका सामना करने के लिए भी केन्द्र और प्रदेश की सरकारें प्रयत्नशील हैं।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सायं 7.00 बजे

मुझे कभी-कभी इस आरोप से पीड़ा होती है कि केन्द्र की सरकार राज्यों के साथ राजनीतिक आधार पर भेदभाव करती है। मैं इस आरोप से इंकार करता हूँ। अगर यह राजनीति का भाग है तो मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन पिछले तीन-चार साल में हमने किसी सवाल पर राज्यों के साथ भेदभाव नहीं होने दिया। सच्चाई तो यह है कि थोड़ा सा आगे जाकर हमने ऐसे राज्यों की भी मदद की है जो राज्य पराये हैं।...*(व्यवधान)* हमारा एन०डी०ए० क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेकर चलता है।

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, कृपया बोलने दें। आप प्लीज़ बैठिये।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तुलना करने के लिए कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। मैंने कोई तर्क जीत लिया इसका मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन जब आरोप लगाए जाते हैं तो उनका समुचित उत्तर देना पड़ता है। 1987 में भी व्यापक सूखा पड़ा था। उस समय की सरकार ने कौन से कदम उठाए थे, उनका मैं उल्लेख करूँगा और आज हम कौन से कदम उठा रहे हैं, इसकी भी चर्चा करूँगा।

1987 में विभिन्न रोज़गार योजनाओं के अंतर्गत 8.7 लाख टन अनाज वितरित किया गया था जबकि चालू वर्ष में हमने संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना के अंतर्गत 19.25 लाख टन अनाज मुफ्त में वितरित किया है। रोज़गार सृजन के लिए 1987 में 842 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे, जबकि इस वर्ष अभी तक लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं, भविष्य में और भी किये जाएंगे।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : विपक्ष की नेत्री बोल रही थीं तो सबने सुना। अब प्रधान मंत्री बोल रहे हैं तो आप सुनेंगे नहीं? बाद में वह भी बोलने वाली हैं, उत्तर दे सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आत शांत रहें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जितना व्यापक और गंभीर रूप सूखे ने इस बार धारण किया है, उसी के अनुसार प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। केन्द्र अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और राज्यों की सहायता कर रहा है। अनेक राज्यों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और इसलिए हम जो भी योजनाएं बना रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि राज्यों के हितों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

काम के बदले अनाज की जो योजना चल रही है उसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत राज्यों को 5000 करोड़ रुपये मूल्य का अनाज प्रति वर्ष दिया जाएगा। शेष 5000 करोड़ रुपये नकद रूप में राज्यों को दिया जाना हैं इसी तरह से प्रदेश सरकारें लघु सिंचाई तथा जन संवर्द्धन की विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर सकती हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी परियोजनाओं को समय रहते पूरा किया जाए जिससे कि सूखे की स्थिति में लोगों को राहत मिल सके।

महोदय, सारे देश में किसानों को ऋण के भार से थोड़ी छूट देने के लिए कदम उठाए गए हैं। फसल पर मिलने वाले ऋण पर ब्याज की वसूली रोक दी गई है। हमने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज सहित फसल ऋण की कोई वसूली नहीं की जाएगी। सूखे की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने किसानों को दिए गए फसल ऋणों की अदायगी में सीधे राहत देने की घोषणा की है। यह लाभ सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों को मिलेगा।

हम नहीं चाहते कि सूखे का राजनीतिकरण किया जाए। इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। इच्छा शक्ति प्रबल है। तत्काल फैसले करने की भी तत्परता है, लेकिन जो तंत्र हमें उत्तराधिकार में मिला है और जिसे हम चार सालों में भी ठीक रास्ते पर नहीं ला सके हैं उसके कारण जगह-जगह पर कठिनाइयां पैदा होती हैं। हमने अनाज दिया, राज्यों को मिल गया, लेकिन राज्यों से जिलों में, तहसीलों में और गांवों में कैसे जाए। कुछ राज्यों ने अपनी कठिनाई बताई। उन्होंने कहा कि अनाज आप हमें दे रहे हैं, वह तो ठीक है और मुफ्त में दे रहे हैं, वह भी ठीक है, लेकिन इसे ले जाने का खर्चा कौन करेगा। हमारे पास तो ले जाने का भी खर्च नहीं है। यह कठिनाई है और उसमें इस बात का ध्यान रख कर फैसले किए गए हैं।

मैं चाहता हूं कि राजनीति को दूर रख कर हम विचार करें। वैसे तो 365 दिन राजनीति चलती है और हमेशा चुनाव होते हैं। कहीं न कहीं वोट की बात सामने आ जाती है, लेकिन सूखा जितना संकट का रूप लेकर आया है उसके चलते हुए जब तक प्रदेश और केन्द्र मिलकर काम नहीं करेंगे और केनद्र में भी सभी राजनीतिक दल संसद में अपना सहयोग नहीं देगे, तब तक संकट से पार पाना मुश्किल होगा। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि वे सूखे से निपटने में सहयोग दें।

श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं हुई। आजकल जो मुख्य मंत्रियों की बैठक होती है, वह भी सर्वदलीय बैठक

होती है। मुख्य मंत्रियों की बैठक होती है। कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी। हम लगातार संपर्क करते रहते हैं, विचार-विनिमय करते रहे हैं और जिन प्रदेशों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार सर्वदलीय समितियों का निर्माण किया है, उनकी हमने सहायता की है, उसमे कोई बाधा पैदा नहीं की, लेकिन राजनीति को लाने के लोभ से थोड़ा बचना चाहिए। चुनाव के वर्ष में कितना हो सकता है, मैं नहीं जानता।

हम सब एक ही बीमारी के मरीज हैं और कभी-कभी मैं सोचता हूं कि यह सूखे की भयावह स्थिति देश कब तक ढोता रहेगा। हर दो-तीन साल के बाद सूखा दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा हैं अनाज नहीं है, चारा नहीं है, पीने का पानी नहीं है। इस परिस्थिति का कोई स्थाई समाधान होना चाहिए।

स्वतंत्रता के बाद इस पर विचार हुआ था, लेकिन उस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया गया। हो सकता है साधनों की कमी का सवाल रहा हो। सब नदियों को जोड़ने का एक प्रयास, जो नदियां जुड़ सकती हैं, जिनको एक-दूसरे के साथ सम्बद्ध किया जा सकता हैं अभी भी 40 फीसदी जमीन में सिंचाई होती है। बाकी का सारा क्षेत्र पड़ा है। जल जीवन है जल के बचत की जितनी योजनाएं अब लागू की जा रही हैं, उन पर पहले से विचार होता तो शायद परिस्थिति भिन्न होती। लेकिन मैं सदन से कहना चाहता हूं, मैं इस बारे में सभी का सहयोग चाहता हूं। आप लोग मिलकर तय करें। मैं आपको निमंत्रण दूंगा कि नदियों को जोड़ने का जो सवाल है, उसमें धन की कमी नहीं होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

सड़कों के लिए जब हमने सड़क अभियान आरंभ किया तो यह कहा गया कि इतना पैसा कहां से आयेगा? पैसा देश में है। पैसा सरकार के पास है लेकिन उसे ठीक तरह से खर्च करने की जरूरत है। नदियों को जोड़ा जा सकता है। पड़ोसी देशों से बात की जा सकती हैं इस सवाल को युद्ध स्तर पर उठाने की जरूरत हैं हम कब तक सूखे का इस तरह से सामना करते रहेंगे? आरोप-प्रत्यारोप होंगे, जन-जीवन कष्टमय होगा। अब तो अन्न की पैदावार बढ़ गयी हैं हमारा किसान, हमारे वैज्ञानिक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन अन्न होते हुए भी कहीं न कहीं से भूख से मरने की खबरें आ जाती हैं। खबरें कितनी सच हैं, कितनी सही हैं, इसका परीक्षण तो बाद में होता है। स्पष्टीकरण दिये जाते हैं लेकिन देश के ऊपर और विदेशों पर तत्काल मानस पर प्रभाव पड़ता है कि कैसा देश है, अन्न के ढेर लगे हुए हैं और भूख से लोग मर रहे हैं।

यह प्रश्न पार्टी का प्रश्न नहीं हैं आज तो ऐसी स्थिति है कि कोई पार्टी कहीं सत्ता में है तो कहीं कोई पार्टी सत्ता में हैं हर सरकार को हमें साथ लेकर चलना है, सबको सहयोग देना है, सबका सहयोग लेना हैं लेकिन भूख से मरने वालों की संख्या को लेकर विवाद होता है कि वह मरा या नहीं मरा? मीडिया का एक ऐसा हिस्सा है जो चाहता है कि लोग मरते रहें, अखबार छपती रहे, अखबार बिकती रहे। यह ठीक नहीं है। मैं इसका विस्तार से उदाहरण नहीं देना चाहता।

उड़ीसा में इस तरह की एक घटना हुई है। कोई वहां फोटो लेने गये थे। उन्हें समाचार मिला कि भूख से मौत हो गई है। वे फोटो लेने के लिए गये और जब उन्होंने देखा कि वह अभी मरा नहीं है तो उन्होंने कहा कि हम फोटो नहीं लेंगे। वह उसके मरने की प्रतीक्षा करते रहे। बाद में पता लगा कि भूख के कारण मरने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अन्न होते हुए भी उसका वितरण ठीक से हो, सब लोगों तक पहुंचे, इसका प्रबन्ध करना तो तंत्र की व्यवस्था का है। इसमें हम कहीं कहीं चूकते हैं। इसका उपाय करना पड़ेगा।

लेकिन मैं आपसे नदियों को जोड़ने की बात कह रहा थ। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में पहल की है, उससे पहले हमारी केन्द्र में बैठक हुई थी। एक प्रैजैंटेशन हुआ था और सरकार से कहा गया, मंत्रालय से कहा गया कि वह एक योजना लेकर आयें। मैं सोनिया जी को आमंत्रित करता हूं कि इस काम में हमारे साथ हाथ बंटाएं, मिलकर काम करें। यह एक ऐसा काम है जो देश की तकदीर को बदल देगा। नदियों को जोड़ना, सूखे की समस्या का स्थायी समाधान है, इसमें समय लगेगा लेकिन समय हमारे पास इतना है कि हम उस काम को पूरा कर सकें। गंगा कावेरी को लेकर एक टॉस्क फोर्स एप्वाइंट किया गया है।

आजकल मैं कावेरी के झगड़े से जुड़ा हुआ हूं। कर्नाटक की बात सुनें या तमिलनाडु की ओर देखें। मामला अदालत में जाता हैं अदालत फैसले करती है मगर समय लगाती है। क्या यह नदी के विवाद हम हल नहीं कर सकते? हरियाणा और पंजाब का भी मामला हैं ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसको मानना चाहिए। लेकिन यह नदियों का पानी कब तक हमारे लिए विवाद का विषय बना रहेगा। मैं समझता हूं कि इस दिशा में सारा सदन सोचना आंरभ करे और हम इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा इस अधिवेशन से, सरकार के कार्यक्रम से हम प्रकट करना चाहते हैं।

और भी कई मुद्दे हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं फिर यही बात कहना चाहता हूं कि सूखे को राजनीति से अलग रखें। सूखे को एक मानवता के सवाल के रूप में देखा जाना चाहिए। पशुओं के लिए चारा नहीं है। चारा हम भेज रहे हैं मगर पर्याप्त नहीं है।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

पीने का पानी नहीं हैं रेलों की व्यवस्था की गई है कि वह फ्री पानी ले जाएं, चारा फ्री ले जाएं, अनाज भी फ्री ले जाने के लिए तैयार हैं। देश में अनाज की कोई कमी नहीं है मगर फिर वितरण की समस्या है और उसमें मैं माननीय सदस्यों को आमंत्रण देता हूं। वे अपने-अपने क्षेत्र के सुझाव दें, प्रदेश की सरकारों को दें। उनकी एक प्रति केन्द्र को भी भेज दें। सूखे का प्रकोप अभी लम्बा चलने वाला हैं अभी एक फसल आ रही है। उसके बाद उसमें कितना घाटा होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है लेकिन हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दृष्टि से यह चर्चा उपयोगी हो, ऐसी मेरी कामना है।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस) : अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी पार्टी की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्ताव, जिसका विषय बहुत ही गंभीर है, विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं इसका समर्थन करना चाहूंगा।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहस के बीच में जो बातें कहीं, हस्तक्षेप के रूप में उन्होंने जो सुझाव दिए, केन्द्र की राजग सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, साथ-साथ प्रदेश सरकारों के साथ किस तरह का समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, उस पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने बल दिया। मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह यह केन्द्र सरकार आश्वासन देती है, चाहे सूखे की परिस्थिति को लेकर, चाहे बाढ़ की परिस्थिति के समय, बाढ़ का प्रकोप जिस तरह किसानों पर होता है, उत्तर बंगाल के चाय बागानों में जिस तरह नुकसान होता है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं। बाढ़ के चलते चाय के पौधे बह जाते हैं, उस तरह सूखे में भी चाय बागानों में चाय के पौधे सूख जाते हैं। हम बार-बार गिड़गिड़ाए। इससे पहले जिस सत्र में भी सूखे पर बहस हुई, बाढ़ के प्रकोप पर बहस हुई या प्राकृतिक आपदा के ऊपर चर्चा हुई, मैंने बोलने की कोशिश की। केन्द्र में जो राजग सरकार है, मैंने उसे बार-बार कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के उत्तर क्षेत्र में जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग एवं कूच बिहार जिलों में जो चाय बागान हैं, जो खेत हैं, वे देश की सम्पत्ति है, अगर उसे बचाना है तो भूटान के साथ बैठना चाहिए और सरकार को इण्डो भूटान जोइंट रीवर कमीशन का गठन करना चाहिए। केन्द्र सरकार आश्वासन देने में सक्षम है, लेकिन उसका कार्यान्वयन कहां तक होता है, इस पर मुझे संदेह हैं इसलिए मैं दोबारा इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अब आश्वासन दीजिए कि गरीब लोगों की जो समस्याएं सूखे और बाढ़ की परिस्थिति की वजह से उत्पन्न होती हैं, उसके लिए आप अपनी बातों को अमल में लाने की जरूर कोशिश करें।

मैं केन्द्र सरकार को दोष न देकर यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप प्रदेश की सरकार के साथ बातचीत करके उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर आपको प्रदेश सरकार का सहयोग मिल जाता है तो आप इसका सही समाधान ढूंढने में समर्थ होंगे, सफल होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी जो सरकार यहां केन्द्र में है, उसकी प्राथमिकता गरीब लोगों के प्रति कम है, बल्कि शायद विनिवेश की जो प्रक्रिया चल रही है, उस ओर ज्यादा ध्यान देने का काम यह सरकार कर रही है। यह सरकार धनिकों को, जिनको मुनाफा आ रहा है, धनिक श्रेणी को मुनाफा और ज्यादा मिले, उस ओर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही है। इस सरकार की आर्थिक नीति को देखने से यही साबित होता हैं इसलिए मुझे संदेह है कि इनकी नीयत और नीति में कहीं यह सरकार फंस न जाये और गरीब लोगों को सूखे की परिस्थिति में जो मदद मिलनी चाहिए, वह मदद उन्हें न मिले। जिन समस्याओं में गरीब जनता, किसान और श्रमिक आज ग्रस्त हैं, उन्हीं समस्याओं से ही हमारे देश की जनता पड़ी न रहे। इसलिए मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि आप जो बोलते हैं, उसे करनी में परिवर्तित कीजिए। आप अपनी कथनी और करनी को एक करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो जनता आपको अगले चुनाव में सही जवाब देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सदन में विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी जो प्रस्ताव लाई हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं जनता (सैकुलर) पार्टी से खड़ा हूं।

सारी बहस तो अच्छी हो गई, पन्थ प्रधान ने भी अच्छी तरह से आश्वासन दिया, लेकिन मुझे याद आता हूं, आप भी महाराष्ट्रियन हैं और महाराष्ट्र के अन्य लोग भी यहां हैं। 1972 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था और सारा महाराष्ट्र उसकी चपेट में आ गया। उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री वसन्तराव नाईक थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने मजदूरों को मजदूरी दी, चारा दिया, पानी की व्यवस्था की, ये सब बातें कर दीं। आपत्ति काल में भी अच्छी व्यवस्था कर दी। जब आपत्ति आई, उस वक्त राजकर्ता ने अच्छी तरह से काम करना तय किया तो आपत्ति काल में भी अच्छी व्यवथा पैदा हो गई।

मेरी सदन से यही प्रार्थना है कि आपत्ति काल में अच्छी व्यवस्था कैसे पैदा की जाये, यह देखना चाहिए। महाराष्ट्र में उस वक्त अकाल पड़ा था, लेकिन इस वक्त 2-3 समस्याएं बहुत गम्भीर हैं गन्ने का किसान भी आज बहुत संकट में हैं भारत सरकार ने बाहर से शुगर